सोवियत संघ में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना

अक्टूबर क्रांति के बार लगभग चालीस वर्षों तक सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में समाजवादी राज्य कायम था। इस समूचे दौर में तीखा वर्ग संघर्ष मौजूद था। इस वर्ग-संघर्ष का प्रतिबिम्बन सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर हो रहा था। पहले लेनिन और बाद में स्तालिन ने गैर सर्वहारा विचारधारा को परास्त करके सर्वहारा वर्ग की विचारधारा को स्थापित किया और समाजवादी समाज की स्थापना और उसका सुदृढ़ीकरण किया था। इस दौरान, गृह युद्ध, साम्राज्यवादियों के आक्रमण इत्यादि की भीषण तबाही-बर्बादी के बीच पूंजीवादी विचारधारा के वाहकों को पराजित करते हुए द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर के आक्रमण को समाजवादी राज्य ने पराजित किया। हिटलर को पराजित करने में सोवियत समाजवादी राज्य की प्रमुख भूमिका थी। इसमें सोवियत जनता को भारी कुर्बानियां देनी पड़ी। हिटलर की पराजय के पश्चात, फिर से सोवियत समाजवादी राज्य तेजी से पुनर्निर्माण के काम को पूरा करने में लग गया। आठ वर्षों के भीतर फिर से समाजवादी समाज के पुनर्निर्माण के काम को पूरा कर लिया गया और सोवियत संघ एक मजबूत ताकत के बतौर उभर कर आया। इसके साथ ही एक समाजवादी खेमा अस्तित्व में आ चुका था। सोवियत संघ की इस ताकत का मुख्य कारण यह था कि वहां मजदूर वर्ग और मेहनतकश अवाम सोवियत राज्य को अपना राज्य समझता था। वे अपने राज्य को बचाने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए कुछ भी कुर्बानी कर सकते थे। और उन्होंने यह किया भी।

1953 में स्तालिन की मौत के बाद सोवियत संघ ने अपना रंग बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी और 1956 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस में ख्रुश्चोव ने व्यक्ति पूजा का विरोध करने के नाम पर सोवियत संघ के समाजवादी राज्य पर हमला बोल दिया और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को एक संशोधनवादी पार्टी में तब्दील करने का कार्यक्रम पेश कर दिया। इसके बाद सोवियत संघ एक समाजवादी राज्य नहीं रह गया। वहां सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को खत्म करके पूंजीवादी अधिनायकत्व में तब्दील कर दिया गया।

आखिर यह कैसे हो गया? क्यों स्तालिन की मौत के तीन वर्ष के भीतर ही संघर्षों में तपी-तपायी बोल्शेविक पार्टी संशोधनवादी दिशा पर चल पड़ी और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व वाले राज्य ने एक पूंजीवादी अधिनायकत्व वाले राज्य में अपना रंग बदल लिया।

ख्रुश्चोव या कोई भी व्यक्ति सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व वाले समाजवादी राज्य को पूंजीवादी अधिनायकत्व वाले राज्य में तब्दील करने और कम्युनिस्ट पार्टी को संशोधनवादी पार्टी में बदलने में तभी सफल हो सकता है, जब समाज के भीतर उसका आधार हो। यदि समाज में पूंजीवादी तत्वों और गैर-सर्वहारा वर्गों का अस्तित्व न हो तो कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रतिगामी परिवर्तन नहीं ला सकता।

सोवियत संघ में समाजवाद के लगभग चार दशकों के समूचे काल के दौरान वर्ग मौजूद थे। मजदूर वर्ग के राज्य के अंतर्गत समाजवादी सार्वजनिक सम्पत्ति के बतौर उद्योगों के साथ-साथ सार्वजनिक सम्पत्ति के दूसरे रूप सामूहिक कृषि फार्म मौजूद थे। सामूहिक कृषि फार्मों के किसानों की स्थिति एक फार्म और दूसरे फार्म में अलग-अलग होती थी। इस रूप में ये उद्योगों की तरह देशव्यापी पैमाने पर एक ही तरह की स्थिति में नहीं थे। ये सामूहिक फार्म से देशव्यापी पैमाने पर एक ही तरह की समाजवादी सार्वजनिक सम्पत्ति में जाने की संक्रमण की स्थिति में थे। इस तरह, समाजवादी समाज में समाजवादी सम्पत्ति के दो रूप मौजूद थे। परिणामतः मजदूर और किसान के बतौर दो अलग-अलग वर्ग मौजूद थे। इसके अतिरिक्त, गांव और शहर और मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम के बीच अंतर मौजूद था।

समाजवादी समाज में 'हर किसी की योग्यता व क्षमता के अनुसार और काम के अनुसार भुगतान' का नियम लागू होता है। वितरण के इस नियम में असमानता अंतर्निहित है। कोई कर्मठ होता है और कोई आलसी, कोई ताकतवर होता है तो कोई कमजोर। ऐसे में ऐसे विभिन्न लोगों को काम के अनुसार भुगतान में असमानता होती है। काम के अनुसार भुगतान एक 'बुर्जुआ अधिकार' है। जब तक समाज ऐसी अवस्था में नहीं पहुंच जाता कि आवश्यकता के अनुसार भुगतान न होने लगे तब तक यह असमानता कायम रहती है।

इसी प्रकार, समाजवादी उद्यमों के बीच विनिमय 'मूल्य के नियम' के अनुसार होते हैं। समाजवादी राज्य मूल्य के नियमों के दायरे को सीमित कर सकता है, लेकिन उन्हें समाप्त नहीं कर सकता। समाजवादी राज्य में मालों का विनिमय मुद्रा के जरिये होता है। माल और मुद्रा की मौजूदगी पूंजीवादी तत्वों को पैदा करती रहती है।

समाजवाद के शुरुआती दिनों में पूंजीवादी विशेषज्ञों को खरीद कर, उन्हें ऊंची तनख्वाहें दी जाती थीं। उत्पादन को सुचारु रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक था। बाद के दिनों में जब मजदूरों के बीच से विशेषज्ञ तैयार होने लगे तो इनमें भी पूंजीवादी विशेषज्ञों की मूल्य-मान्यतायें और जीवन शैली स्थापित होने लगी। ये विशेषज्ञ भी व्यापक मजदूरों से अलग-थलग एक तबके के बतौर अपने को समझने लगे थे।

लेनिन ने अक्टूबर क्रांति के सम्पन्न होने के बाद बार-बार कहा था कि पराजित शोषक वर्ग अपने छीने गये "स्वर्ग" को वापस पाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। उनके अनुसार, छोटे पैमाने का उत्पादन और निम्न पूंजीवादी वातावरण निरंतर, हर रोज, हर घंटे पूंजीवाद के नये तत्व पैदा करता रहता है। पूंजीवादी प्रभाव तथा निम्न पूंजीपति वर्ग का पतनशील माहौल राज्यसत्ता में बैठे राजनीतिक तौर पर पतित तत्वों और नये पूंजीवादी लोगों को पैदा करने में मदद पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर साम्राज्यवादियों की घेरेबंदी समाजवादी समाज को बाहर से तोड़ने के लिए हमेशा कोशिश में लगी रहती है।

सोवियत संघ प्रथम समाजवादी देश था। उसके पास पहले से समाजवादी समाज के निर्माण की कोई मिसाल नहीं थी। ऐसे में गलतियों का होना लाजिमी था। दुनिया की कोई भी पार्टी या नेता गलतियों से बच नहीं सकता। स्वाभाविक था कि समाजवादी निर्माण के दौरान गलतियां हुईं थीं। स्तालिन के नेतृत्व के काल में कई सारी ऐसी गलतियां थीं जिनसे बचा जा सकता था। उनमें सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने 1936 में और बाद में 1938 में जब यह कहा कि सोवियत संघ में "दुश्मनीपूर्ण वर्गों" का अस्तित्व नहीं रह गया है, कि सोवियत समाजवादी समाज में मजदूर वर्ग, किसान और बुद्धिजीवी समुदाय के मित्रतापूर्ण वर्ग रहते हैं। तब उन्होंने सोवियत समाज में वर्गों और वर्ग अंतर्विरोधों के दुश्मनीपूर्ण चरित्र ग्रहण करने की संभावना से इंकार कर दिया। लेकिन व्यवहार में वे पार्टी और राज्य के भीतर पूंजीवादी दृष्टिकोण अपनाने वालों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे थे। इस गलती के अतिरिक्त, उनकी रचनाओं में, यहां तक कि अंतिम रचना 'सोवियत संघ में समाजवाद की आर्थिक समस्यायें' में भी, उत्पादक शक्तियों के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है। उत्पादन सम्बन्धों में क्रांतिकारी रूपान्तरण के बारे में कोई बात नहीं है। इस रचना में स्तालिन यह तो स्वीकार करते हैं कि समाजवादी समाज में उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों के बीच कुछ असंगति आ सकती है। लेकिन इससे आगे वह नहीं जाते। इसलिए मामले की तह तक जाने में वे असफल रहते हैं। हालांकि वे अपने जीवन के अंतिम समय तक सर्वहारा कार्यदिशा और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के समाजवादी राज्य के निर्माण की दिशा में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते रहे। लेकिन मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विज्ञान के धरातल पर हुई इस गलती से गम्भीर कीमत आगे चुकानी पड़ी।

द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के तकरीबन 35 लाख सदस्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध में शहादत दी थी। ये पार्टी के अनुभवी, आत्म-बलिदान की भावना से ओतप्रोत सर्वहारा वर्ग के अग्रिम कतारों के लोग थे। विश्व युद्ध के दौरान जो लोग पार्टी में भर्ती हुए थे, उनकी बहादुरी और आत्मबलिदान की भावना तो काबिलेतारीफ थी, लेकिन ये गुण अनुभव और सर्वहारा दृष्टिकोण की भरपाई नहीं कर सकते थे। पार्टी में ये नई भरती नाजी कब्जे के दौरान हुई थी जिसमें कम्युनिस्टों को चुन-चुन कर मारा जाता था। ये नयी भर्तियां महान देशभक्ति पूर्ण युद्ध के दौरान होने से इन सदस्यों में सर्वहारा दृष्टिकोण का व्यापक अभाव था।

इसलिए, 1947-53 के दौरान पार्टी कतारों में विजातीय प्रवृत्तियां काफी बढ़ गयीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के साथ मोर्चा बनने का भी पूंजीवादी प्रभाव सोवियत सैनिकों और नागरिकों पर पड़ा था। उस दौरान, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के पतित लोगों की राज्य मशीनरी और प्रशासनिक पदों से छंटनी करने तथा नयी भर्तियों को सीमित करने की कोशिश की गयी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के राजनीतिक-वैचारिक स्तर को उन्नत करने पर जोर दिया गया था। उस समय यह कहा गया था कि पार्टी की संख्यात्मक वृद्धि के मुकाबले पार्टी का विचारधारात्मक राजनीतिक स्तर बहुत निम्न है।

पार्टी के नेतृत्वकारी पदों पर पूंजीवादी विचार किस कदर प्रभाव डाल रहे थे इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। सोवियत संघ के योजना आयोग (गोस्प्लान) कि अध्यक्ष और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिटब्यूरो के सदस्य वोज्नेसेंस्की ने उस समय कहा था कि सोवियत अर्थव्यवस्था एक हद तक बाजार की मांगों और मूल्य के नियम द्वारा संचालित होती है, लेकिन इसको और ज्यादा छूट देने की जरूरत है। उसके अनुसार कीमतों को उत्पादन की लागत को प्रतिबिंबित करना चाहिए जिससे कि मूल्य का नियम उत्पादन को स्वतंत्रतापूर्वक संचालित कर सके। वह इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि योजना को मजदूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और न ही मजदूरों के नियंत्रण के वह पक्ष में था। 1947 और 1949 के बीच उसने अपनी कुछ धारणायें व्यवहार में लागू कीं। 1948 में उसने प्रस्तावित किया कि पूंजीगत मालों की बिक्री उनकी उत्पादन की कीमत के आधार पर होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उनके "मूल्यों" के आधार पर होनी चाहिए। बाद में उसी वर्ष उसने पंचवर्षीय योजना में अलग-अलग उद्यमों की स्वायत्तता को बहाल करने और केन्द्रीय योजना मशीनरी को कमजोर करने का प्रस्ताव पेश किया जबकि समाजवादी राज्य में उत्पादन का लक्ष्य मजदूर वर्ग और मेहनतकश अवाम की जरूरतों को पूरा करना होता है। समाजवादी राज्य कुछ उत्पादनों को उत्पादन लागत से कम दाम पर लोगों को उपलब्ध कराता है और कुछ उत्पादों का वह उत्पादन लागत से ज्यादा दाम रख सकता है। यहां मूल्य का नियम, पूंजीवादी उद्यमों की तरह कीमतों का निर्धारण नहीं करता। समाजवादी राज्य मूल्य के नियम को सीमित करता है।

स्तालिन ने इसका जोरदार खंडन किया। यह कहा जाता है कि उन्होंने बोज्नेसेंस्की से कहा "तुम रूस में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना करना चाहते हो।" इसके बाद बोज्नेसेंस्की को उसके पदों से हटा दिया गया और उसको गिरफ्तार करके उसे मौत की सजा दे दी गयी।

यहां पर लेख का मकसद स्तालिन का समग्र मूल्यांकन करना नहीं है। यहां सिर्फ इस बात की चर्चा की गयी है कि स्तालिन अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के अंतर्गत समाजवादी समाज के निर्माण और सुदृढ़ीकरण करने में लगे रहे। उन्होंने जो गलतियां कीं वह सर्वहारा वर्ग के नेता द्वारा की गयी विज्ञान की गलतियां थीं, जिनके कारण तथा अन्य वस्तुगत हालात, जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है, सोवियत संघ में तीन साल में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व वाले राज्य की पूंजीवादी अधिनायकत्व वाले राज्य में तब्दीली हो गयी।

लेकिन यह तब्दीली अपने आप नहीं हो गयी। यह सोवियत संघ के समाजवादी समाज में मौजूद वर्ग-संघर्ष तथा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर इसके प्रतिबिंबन को व्यक्त करती है। समाजवादी राज्य के पूंजीवादी राज्य और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के संशोधनवादी पार्टी बनने के सामाजिक आधार की यहां चर्चा की गयी है।

लेकिन जहां यह सच है कि बिना सामाजिक आधार के पूंजीवादी पुनर्स्थापना नहीं हो सकती थी, वहीं यह भी एक सच्चाई है कि इस सामाजिक आधार ने क्रमशः अपने को ताकतवर बना कर सोवियत समाजवादी समाज को पूंजीवादी समाज में नहीं रूपान्तरित किया।

इसके लिए आवश्यक था कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को लागू करने वाली सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व पर कब्जा किया जाय तथा तख्तापलट को अंजाम दिया जाय। किले पर कब्जा करने का सबसे कारगर तरीका किले के भीतर से कब्जा करना है। बाहर से सोवियत समाजवादी राज्य को ध्वस्त नहीं किया जा सकता था। हिटलर की नाजी जर्मनी के द्वारा सोवियत समाजवादी दुर्ग को ध्वस्त करने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी और खुद हिटलर की नाजीशाही ध्वस्त हो चुकी थी। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व वाले राज्य को भितरघाती ही ध्वस्त कर सकते थे। भितरघातियों के इस समूह का मुखिया निकिता ख्रुश्चोव था, जिसने किले के भीतर से सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व वाले राज्य पर हमला बोला था।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस और बाद का ख्रुश्चोव का काल

स्तालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर मौजूद सभी दैत्य और दानव उभर कर सामने आये। वोज्नेसिंस्की जैसे लोग, जो अभी तक चुप्पी लगाये बैठे थे और दो मुँहे थे, मौका मिलते ही वे गोलबंद होकर बाहर आये तथा सोवियत समाजवादी समाज की राज्यसत्ता पर और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व पर कब्जा कर लिया। इस संघर्ष में उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग भी किया। कुछ लोगों की हत्याएं करके उन्हें किनारे लगाया गया। अखिरकार, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस में इस गुट के शीर्ष पर बैठे निकिता ख्रुश्चोव ने अपनी गुप्त रिपोर्ट पेश की। इसमें स्तालिन पर "व्यक्ति पूजा" के नाम पर व्यापक हमला बोला गया। स्तालिन पर अकस्मात हमला वस्तुतः मजदूर वर्ग के शासन पर हमला था। 30 वर्षों तक स्तालिन के नेतृत्व में कायम सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व वाले राज्य पर हमला था। इससे ख्रुश्चोव की मंशा स्पष्ट हो गयी। हालांकि अभी उसने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की पाखण्डपूर्ण माला जपना जारी रखा था। लेकिन 1961 तक आते-आते उसने सोवियत राज्य को "सम्पूर्ण जनता का राज्य" और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी को "समूची जनता की पार्टी" कहना शुरू कर दिया। उसने "सम्पूर्ण जनता का राज्य" और "सम्पूर्ण जनता की पार्टी" का सूत्रीकरण सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 22वीं कांग्रेस में किया। यह अब स्पष्ट हो गया था कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता के शीर्ष पर बैठे पूंजीवादी पथगामियों की पार्टी हो गयी थी। और सोवियत राज्य सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व वाला राज्य न रह कर एक पूंजीवादी अधिनायकत्व वाले राज्य में तब्दील हो गया था। दरअसल यह तो 1956 की बीसवीं कांग्रेस में ही हो चुका था। लेकिन रंगे सियार की तरह वह उस समय सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की दुहाई दे रहा था।

"सम्पूर्ण जनता का राज्य" और "समूची जनता की पार्टी" की अवधारणा के पीछे उसने यही तर्क दिया था कि सर्वहारा वर्ग और समूची जनता में कोई अंतर नहीं है क्योंकि सोवियत संघ में मजदूर, किसान और क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों के बीच कोई अंतर नहीं है। उसने मार्क्स के इस कथन कि पूंजीवाद और कम्युनिज्म के बीच एक लम्बा ऐतिहासिक संक्रमण काल रहता है और इसी के साथ ही एक राजनीतिक संक्रमण काल होता है जिसमें राज्य सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, को धता बताते हुए अपनी संशोधनवादी दिशा पेश कर दी थी।

स्तालिन पर चौतरफा हमला बोलते हुए उसने यह कभी भी नहीं बताया था कि स्तालिन की विचारधारात्मक-राजनीतिक या सांगठनिक क्या गलतियां थीं और उन्हें उन्हें दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए था, यह उसने कभी पेश नहीं किया। बल्कि उसने स्तालिन की उस गलती का इस्तेमाल किया जिसमें स्तालिन ने कहा था कि सोवियत समाजवादी समाज में दुश्मनीपूर्ण वर्ग नहीं रह गये हैं। उसने स्तालिन की इस गलती का इस्तेमाल सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के राज्य को पूंजीवादी अधिनायकत्व वाले राज्य में तब्दील करने में किया। उसने स्तालिन के साथ दुश्मनों वाला व्यवहार करके उनकी गलतियों का इस्तेमाल किया। दुश्मन एक-दूसरे के साथ यही करते हैं। वे अपने दुश्मन की गलतियां नहीं बताते बल्कि उनका इस्तेमाल अपने हित में करते हैं। ख्रुश्चोव, जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के राज्य का और मजदूर वर्ग की हिरावल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का घोर विरोधी था और उसने पूंजीवादी पुनर्स्थापना करने में सबसे पहले मजदूर वर्ग को विचारधारात्मक-राजनीतिक -सांगठनिक तौर पर निरस्त्र करने के लिए सबसे पहले इन संस्थाओं पर हमला किया और इनका चरित्र पूंजीवादी कर दिया। हालांकि वह सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का लेबल लगाये हुए था। यह लेबल मजदूर वर्ग और सोवियत मेहनतकश जनता को धोखा देने के लिए था।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद हमें शिक्षा देता है कि राज्य की अवधारणा एक वर्गीय अवधारणा है। वह यह बताता है कि हर राज्य में एक विशेष वर्ग का अधिनायकत्व रहता है और वह अन्य वर्गों के उत्पीड़न-दमन का हथियार होता है। समाजवादी राज्य भी इसका अपवाद नहीं है। इसमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व कायम रहता है। यह पूंजीवादी वर्गों व तबकों के ऊपर दमन का हथियार होता है। जब तक राज्य अस्तित्वमान रहता है, तब तक वह वर्गों से ऊपर नहीं हो सकता और इस तरह वह समूची जनता का राज्य नहीं हो सकता।

इसी प्रकार, कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग की हिरावल पार्टी होती है। वह मजदूर वर्ग के सबसे वर्ग-सचेत और कम्युनिज्म की भावना से ओत-प्रोत लोगों से लेकर बनती है। मजदूर वर्ग की पार्टी का गठन और उसका निर्माण मार्क्सवाद-लेनिनवाद के क्रांतिकारी सिद्धान्त के अनुसार किया जाता है और उसकी कार्यशैली क्रांतिकारी तरीके से निर्मित होती है। कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग के संगठन का सर्वोच्च रूप होती है। कम्युनिस्ट पार्टी में अन्य वर्गों के सदस्य भर्ती हो सकते हैं, लेकिन वे अपने वर्ग-दृष्टिकोण को छोड़कर सर्वहारा वर्ग के दृष्टिकोण को अपना कर ही भर्ती हो सकते हैं।

लेकिन संशोधनवादी ख्रुश्चोव गुट ने समूची जनता की पार्टी की अवधारणा पेश करने के पीछे 1963 के समाचार पत्रों में यह तर्क दिया था कि वह समूची जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, कि समूची जनता मजदूर वर्ग के मार्क्सवादी-लेनिनवादी विश्व दृष्टिकोण को अपना चुकी है, तथा मजदूर वर्ग का ध्येय-कम्युनिज्म का निर्माण-समूची जनता का ध्येय बन चुका है, कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की कतारों में मजदूरों, सामूहिक किसानों और बुद्धिजीवियों के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की कतारों में सौ से अधिक जातियों और कबीलों के प्रतिनिधि एकताबद्ध हैं, और कि पार्टी की गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाला जनवादी तरीका भी समूची जनता की पार्टी के स्वरूप के अनुरूप है।

संशोधनवादी ख्रुश्चोव गुट का समूची जनता की पार्टी के बारे में यह दृष्टिकोण पूर्णतया मार्क्सवाद विरोधी था। यह मार्क्सवाद-लेनिनवाद की इस बुनियादी शिक्षा से पूर्णतया विरोध में है कि समाजवादी समाज में वर्ग, वर्ग अंतरर्विरोध और वर्ग संघर्ष मौजूद रहता है। यह एक संक्रमणकालीन समाज होता है, जिसमें पूंजीवाद के भी तत्व रहते हैं और कम्युनिज्म के तत्व भी लगातार बढ़ते रहने की प्रक्रिया में रहते हैं। यदि सर्वहारा वर्ग की पार्टी सर्वहारा अधिनायकत्व को जीवन के हर क्षेत्र मे सही तरीके से लागू करती है तो इस बात की गारण्टी की जा सकती है कि वह क्रमशः कम्युनिज्म की ओर आगे बढ़ती जायेगी और पूंजीवादी तत्वों को क्रमशः विनाश की ओर ले जायेगी। इसलिए सर्वहारा वर्ग की पार्टी और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की आवश्यकता समूचे समाजवादी काल में बनी रहती है। समाजवादी समाज के पूरे दौर में ये अंतिम तौर पर नहीं तय होता कि समाजवाद विजयी हो गया है कि पूंजीवाद। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पूंजीवादी तत्व आते रहते हैं और समाज के सुविधा प्राप्त हिस्से का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। वे कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर पूंजीवादी कार्यदिशा लागू करने की कोशिश करते रहते हैं। समूचे समाजवादी काल में पूंजीवादी रास्ते और समाजवादी रास्ते के बीच जीवन मरण का संघर्ष चलता रहता है। कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वहारा चरित्र इस बात को सुनिश्चित करता है कि वह सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को समूचे समाजवादी समाज के दौरान मजबूत करे न कि उस कमजोर करे।

संशोधनवादी ख्रुश्चोव गुट द्वारा यह कहना कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी समूची जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, सरासर बकवास है और मार्क्सवाद-लेनिनवाद विरोधी बात है। यह समाजवादी समाज में वस्तुगत तौर पर मौजूद वर्ग-संघर्ष से इंकार करना था। इसी प्रकार उसका यह कहना कि सोवियत संघ में मजदूर वर्ग के विश्व दृष्टिकोण को समूची जनता अपना चुकी है और मजदूर वर्ग के ध्येय-कम्युनिज्म के ध्येय- को उसने अपना ध्येय बना लिया है, यह भी उसी तरह की बकवास है। क्या सोवियत समाज की पूरी आबादी का विश्व-दृष्टिकोण मार्क्सवादी-लेनिनवादी हो गया था? इस तरह की बकवास अकल्पनीय लगती है, लेकिन यह सच थी। क्योंकि पूंजीवादी पुनर्स्थापना के अपने कार्यक्रम को पेश करते समय कोई मार्क्सवादी-लेनिनवादी अवस्थिति में कितना भी घुमावदार, जलेबी जैसे गोल-गोल तर्क पेश करे, वह हास्यास्पद तरीके से अतार्किक बातें करने के लिए अभिशप्त होता है। संशोधनवादी ख्रुश्चोव गुट 1961 में यह भी कहने लगा था कि सोवियत समाज अब कम्युनिज्म की ओर जा रहा है कि वह अगले बीस वर्षों में कम्युनिस्ट समाज का निर्माण बुनियादी तौर पर पूरा कर लेगा। एक तरफ, वह विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक पूंजीवादी वर्ग को बढ़ावा दे रहा था। तो दूसरी तरफ वह वर्गों के बीच के वस्तुगत संघर्ष से इंकार करके कम्युनिस्ट समाज के निर्माण की बात कर रहा था। यह और कुछ नहीं था बल्कि पूंजीवादी पुनर्स्थापना पर धूम्रावरण डालने की और सोवियत मजदूर वर्ग की आंखों में धूल झोंकने की उसकी कोशिश थी। मार्क्सवाद-लेनिनवाद से अपनी गद्दारी को छिपाने की उसकी चाल थी।

ख्रुश्चोव ने 20वीं पार्टी कांग्रेस में मार्क्सवाद-लेनिनवाद पर जो दूसरा सबसे बड़ा हमला किया वह "तीन शांतिपूर्ण" सिद्धान्त को पेश करना था-"शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व", "शांतिपूर्ण प्रतियोगिता" और "शांतिपूर्ण संक्रमण" का सिद्धान्त। "शांतिपूर्ण सहअस्तित्व" की दो विपरीत समाज व्यवस्थाओं की लेनिन द्वारा प्रतिपादित तत्कालीन कार्यनीति को ख्रुश्चोव ने सोवियत विदेश नीति की आम कार्यदिशा बना दिया। इस आम दिशा का मतलब था कि अब सोवियत संघ पूंजीवादी देशों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में रहने के लिए उत्पीड़ित जनता व उत्पीड़ित राष्ट्रों के मुक्ति संघर्षों का सक्रिय समर्थन करने से अपने को रोक सकता है। यह साम्राज्यवाद के विरुद्ध उस समय चल रहे विश्वव्यापी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों से मुंह मोड़ लने की कार्यदिशा थी। "शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता" और "शांतिपूर्ण संक्रमण" की आम दिशा का कुल मतलब यह निकलता था कि दुनिया के उत्पीड़ित राष्ट्र और पूंजीवादी दुनिया का मजदूर वर्ग क्रांति के रास्ते को त्याग कर पूंजीवादी संसदों के भीतर अपने को बहुमत में लाने की कोशिश करें तथा पूंजीवादी संसदों के माध्यम से समाजवाद का निर्माण करें। यह विशुद्ध रूप से मार्क्सवाद-लेनिनवाद को बर्नस्टीन और काउत्स्की के संशोधनवाद से प्रतिस्थापित करना था। उसने अपनी पार्टी कांग्रेस की इस संशोधनवादी कार्यदिशा को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन पर थोपने की कोशिश की थी। ख्रुश्चोव के द्वारा प्रतिपादित ये "तीन शांतिपूर्ण" सिद्धान्त सोवियत संघ में पूंजीवादी पुनर्स्थापना करने के उसके प्रयासों का ही हिस्सा थे।

ख्रुश्चोव ने सर्वप्रथम सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत समाजवादी राज्य की संस्थाओं पर कब्जा करके उन्हें अपने संशोधनवादी कार्यक्रम को लागू करने के अनुरूप ढालने की कोशिश की। इसमें उसे विरोध का सामना करना पड़ा। उसने इसके

लिए पार्टी और राज्य के शीर्षस्थ पदों पर लोगों की बड़े पैमाने पर छंटनी की। उन्हें अपने पदों से बर्खास्त किया गया। राज्य सत्ता और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी पर कब्जा करने के बाद उसने अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी रास्ते पर ले जाने की ओर प्रयास किया। अन्यथा हो ही नहीं सकता था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि सोवियत समाजवादी राज्य के और पार्टी के अंदर कुछ पथभ्रष्ट, सार्वजनिक सम्पत्ति को अपने फायदे में इस्तेमाल करने वाले तथा अपने उद्यम या सामूहिक फार्म के संकीर्ण हितों के लिए काम करने वाले लोग थे। ये सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के राज्य के अंदर रहते वे पूंजीवादी तौर तरीके और जीवन शैली को अपनाये रहते थे और इनकी सारी गतिविधियां छिपे तौर पर होती थीं। क्योंकि इन्हें हमेशा पकड़े जाने और सजा पाने का डर रहता था। बोज्नेसेंस्की जैसे बहुत उदाहरण इनके सामने थे। लेकिन ख्रुश्चोव के सत्तासीन होने के बाद जब उसने अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी कदम उठाने शुरू किये, तब ऐसे तत्वों को खुल कर खेलने का मौका मिला।

ख्रुश्चोव ने सबसे पहले सामूहिक खेती पर हमला किया। चूंकि सामूहिक खेती समाजिक मालिकाने का निम्न रूप थी। इसका उच्च रूप राज्य फार्म थे। यह वह मर्मस्थल था जहां सबसे पहले चोट की जा सकती थी। ये सामूहिक फार्म कृषि उत्पादों का बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादित करते थे। इनमें किसानों की भारी संख्या सहकारिता के आधार पर फार्मों पर काम करती थी और सामूहिक तौर पर इसकी मालिक थी। ये अपने उत्पाद को सोवियत राज्य को बेचते थे। सोवियत राज्य की यह हमेशा कोशिश होती थी कि इन सामूहिक फार्मों को राज्य फार्म में तब्दील करने की आवश्यक परिस्थितियां तैयार की जायं। मजदूर-किसान एकता को बढ़ाने और सामूहिक फार्मों को राज्य फार्म में तब्दील करने के लिए सोवियत राज्य ने राज्य के मालिकाने वाले मशीन -ट्रैक्टर स्टेशन (एम.टी.एस.) का एक तानाबाना खड़ा किया था। यह तानाबाना सामूहिक फार्मों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के साथ साथ उनको कृषि सम्बन्धी जानकारी और अक्सर राजनीतिक दिशा निर्देश देता था। 1957 में ख्रुश्चोव ने इस महत्वपूर्ण संस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने एम.टी.एस. (मशीन ट्रैक्टर स्टेशन) की सम्पत्ति सामूहिक फार्मों को बेचने का आदेश दे दिया। इसने ज्यादा सम्पन्न सामूहिक फार्मों की मदद की। विपन्न फार्मों की स्थिति इससे और खराब हो गयी। इस कदम ने सम्पन्न और विपन्न फार्मों के बीच दूरगामी और समानता पूर्ण तकनीकी विकास के किसी आधार को ही नष्ट कर दिया। इसने समूहिक फार्मों पर केन्द्रीय योजना आयोग के नियंत्रण को भी कमजोर कर दिया। इस तरह इसने अर्थव्यवस्था में अराजक पूंजीवादी तत्वों को मजबूत किया और प्रत्येक सामूहिक फार्म के भीतर पूंजीवादी विशषज्ञों और प्रबन्धकों के प्रभाव को और ज्यादा मजबूत कर दिया।

ख्रुश्चोव ने सामूहिक फार्मों और राज्य फार्मों के बीच किसी भी तरह के अंतर से इंकार किया। 1958 से पहले जो थोड़े से राज्य फार्म अस्तित्वमान थे, वे आर्थिक और राजनीतिक तौर पर विकसित इकाइयां होती थीं। लेकिन एम.टी.एस. को तोड़ देने के बाद ख्रुश्चोव ने सबसे कमजोर और पिछड़े सामूहिक फार्मों को, ऐसे सामूहिक फार्मों को जो आधुनिक मशीनरी खरीदने की स्थिति में नहीं थे, राज्य फार्म में तब्दील करने का फैसला किया। वस्तुतः ऐसे फार्म राज्य द्वारा कल्याणकारी रकम प्राप्त करने वाले हो गये। ये खुद अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ थे। इनको राज्य की एक किस्म की खैरात पर पलने वाला बना दिया गया जिनका भविष्य ठहराव के अलावा और कुछ नहीं था।

इसी के साथ साथ ख्रुश्चोव ने सम्पन्न सामूहिक फार्मों के विकास को प्रोत्साहित किया और इनके भीतर सामूहिक फार्मों के अध्यक्षों और अन्य अधिकारियों की हैसियत को मजबूत किया। इसका परिणाम यह निकला कि लोग राज्य फार्मों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे। इस प्रकार, राज्य फार्म प्रणाली को कमजोर किया गया और पूंजीवाद की स्वतःस्फूर्त शक्तियों को अधिक मजबूत किया गया। ज्यादा विकसित सामूहिक फार्मों में पूंजीवाद की स्वतःस्फूर्त शक्तियों को बेलगाम छोड़ दिया गया। इन सबसे ख्रुश्चोव सम्पन्न सामूहिक फार्मों पर अपना आधार बनाने में कामयाब हो गया।

और जैसे कि इतना ही पर्याप्त न रहा हो, 1953-59 के वर्षों के दौरान ग्रामीण पूंजीवाद को और ज्यादा गति देने के लिए निजी जमीन के टुकड़ों, निजी पालतू जानवरों और सामूहिक फार्मों में काम की जरूरतों पर लगे प्रतिबंधों में भारी रियायतें दी गयीं। 1966 तक एक सोवियत पैरोकार पोमेरॉय के अनुसार, खेती की जाने वाली महज 3% निजी जमीन में आलू उत्पादन का 60%, गोश्त और हरी सब्जियों का 40%, दूध का 39% और अंडों का 68% उत्पादन होता था।

ख्रुश्चोव ने समाजवादी कृषि को पंगु बना देने के बाद अब अपनी निगाह खुद केन्द्रीय योजना पर केन्द्रित की। एक ही चोट से उसने केन्द्रीय नियोजन मंत्रालयों को बंद कर दिया और उनकी जिम्मेदारियों को सौ से ज्यादा बिखरी हुई आर्थिक परिषदों के ऊपर डाल दिया। ये आर्थिक परिषदें क्षेत्रीय मंत्रालय थीं। नौकरशाहाना तरीके से नौकरशाही विरोधी आवरण के तहत केन्द्रीय नियोजन को बंद किया गया था। इन आर्थिक परिषदों पर स्थानीय नियंत्रण था। इसका परिणाम यह हुआ कि सचेत, तालमेलभरी योजना पर स्थानीय स्वार्थ हावी हो गये और राजनीतिक दिशा-निर्देश पर विशेषज्ञता प्रभावी हो गयी। समूची अर्थव्यवस्था का दरवाजा मुनाफा नाम के महान "नियामक" को फिर से लागू करने के लिए खुला छोड़ दिया गया।

जैसा कि ऊपर कई बार कहा जा चुका है कि ख्रुश्चोव ने सर्वप्रथम पार्टी पर कब्जा किया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर ऊपर बताये गये हमले कभी भी सफलतापूर्वक लागू नहीं किये जा सकते थे, यदि ख्रुश्चोव एण्ड कम्पनी ने कम्युनिस्ट पार्टी पर कब्जा और उसे नष्ट नहीं कर दिया होता। यह सर्वहारा वर्ग के वफादार सदस्यों की बर्खास्तगी, सभी स्तरों पर ईमानदार कम्युनिस्टों की व्यापक छंटनी की महज शुरूआत थी। 1952 में हुई 19वीं कांग्रेस में चुने गये केन्द्रीय कमेटी के लगभग 70 फीसदी सदस्यों को 1961 में हुई 22वीं कांग्रेस में बाहर कर दिया गया। यह निचले स्तर पर और ज्यादा छंटनी को प्रतिबिंबित करता है।

इसी के साथ ही ख्रुश्चोव ने पार्टी का दरवाजा उन लोगों के लिए खोल दिया जो सर्वहारा वर्ग की आगे बढ़ी हुई टुकड़ी का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ये वास्तव में ऐसे लोग थे जो शब्दों में समाजवाद को स्वीकार करते थे, लेकिन कामों में पूंजीवादी पुनर्स्थापना के समर्थक थे। स्तालिन पूंजीवादी तत्वों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते थे जबकि ख्रुश्चोव की नीति ठीक इसके विपरीत थी। ख्रुश्चोव ने पार्टी की भर्ती पर पहले से लगे प्रतिबंधों को ढीला कर दिया और बड़े पैमाने पर पार्टी में नयी भर्ती शुरू की। लेनिन और स्तालिन के जमाने की भर्ती में राजनीतिक दिशा पर ज्यादा जोर रहता था, लेकिन ख्रुश्चोव ने तकनीकी विशेषज्ञता पर ज्यादा जोर दिया। इस प्रकार पार्टी क्रमशः सफेदपोश लोगों और तकनीकी विशेषज्ञों की पार्टी बनती गयी। सर्वहारा वर्ग की राजनीति का परित्याग करके वह व्यवहार कुशल विशेषज्ञों की पार्टी बनाने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों का प्रमुख काम राजनीतिक दिशा देना नहीं बल्कि अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए उत्पादन को बढ़ाना था। इससे और आगे बढ़कर उसने पार्टी का दो क्षेत्रों में "औद्योगिक पार्टी" और "कृषि पार्टी" में नकली तरीके से विभाजन कर दिया। इससे पार्टी के कार्यकर्ता उत्पादन के प्रबन्धन में लग गये और राजनीतिक दिशा देने के मामले में उनकी भूमिका गौण होती गयी।

उत्पादन के आधार पर पार्टी गठित करने के बारे में ख्रुश्चोव गुट का तर्क यह था कि समाजवाद में राजनीति पर अर्थनीति की प्रधानता होती है। इस गुट के अनुसार, पार्टी संगठनों के काम की मुख्य विषयवस्तु उत्पादन है। ख्रुश्चोव का यह विचार पूर्णतया लेनिनवाद विरोधी है।

त्रात्स्की और बुखारिन की आलोचना करते हुए लेनिन ने कहा था :

> "राजनीति अर्थनीति की केन्द्रित अभिव्यक्ति है। ... ... राजनीति का अर्थनीति के मुकाबले अनिवार्यतः अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके विपरीत दलील देने का मतलब है मार्क्सवाद की प्रारम्भिक जानकारी को भी भूल जाना।

उन्होंने आगे कहा था :

> " ... ... किसी विषय के बारे में एक निश्चित राजनीतिक रुख अपनाये बिना कोई भी वर्ग अपने शासन को कायम नहीं रख सकता तथा इसके परिणामस्वरूप अपनी उत्पादन की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता।"

(लेनिन, ट्रेड यूनियनों पर, वर्तमान परिस्थिति पर, तथा त्रात्स्की और बुखारिन की गलतियों पर फिर एक बार विचार" महान बहस, 354-355 में उद्धृत, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन)

इस तरह से ख्रुश्चोव गुट ने पार्टी सदस्यों को राजनीति से वंचित कर दिया तथा ग्रामीण इलाकों में सामूहिक फार्मों के अध्यक्षों और पूंजीवादी विशेषज्ञों के नेतृत्व में उनका काम उत्पादन को संगठित करने का कर दिया।

कुल मिलकर ख्रुश्चोव ने, 20वीं 21वी और 22वीं कांग्रेस के दौरान सार्वजनिक उद्यमों को मुनाफे के आधार पर संगठित करने, केन्द्रीय योजना मंत्रालयों को तोड़कर उन्हें स्थानीय मंत्रालयों या आर्थिक परिषदों में संगठित करके योजनाओं को बाजार की शक्तियों और मूल्य के नियमों के हवाले करने, ग्रामीण इलाकों में सामूहिक फार्मों को और ज्यादा आजादी देकर उन्हें मुनाफे के लिए काम करने तथा निजी खेती के टुकड़ों को प्रोत्साहित करने जैसे कदमों से पूंजीवादी पुनर्स्थापना को अंजाम दिया।

ख्रुश्चोव की इस कार्यदिशा से मजदूरों में असंतोष बढ़ा। उत्पादन में गिरावट आयी और वर्ग अंतर्विरोध तेज हुए तथा समय-समय पर हड़तालों और प्रदर्शनों की खबरें बढ़ने लगीं। पार्टी और राज्य के पदों पर बैठे लोग गबन और धोखाधड़ी के जरिये करोड़ों रूबल इकट्ठे करके भूमिगत उद्यम खड़ा करने लगे। वैसे कहने के लिए और स्वरूप में सोवियत संघ के अधिकांश उद्यम अब भी राज्य की सम्पत्ति थे। सामूहिक फार्म अब भी वहां के किसानों की सहकारी सम्पत्ति थे जो कि एक तरह की सामाजिक सम्पत्ति थी, हालांकि वह निम्न स्तर की थी। लेकिन इनकी अंतर्वस्तु बदलकर पूंजीवादी हो गयी थी।

1964 में ख्रुश्चोव को हटा कर ब्रेझनेव और कोसीगिन सत्तासीन हो गए।

ब्रेझनेव-कोसीगिन काल- पूंजीवादी पुनर्स्थापना का पूर्ण रूप से विस्तार

ख्रुश्चोव ने समाजवादी व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था। लेकिन उसकी अंतरविरोधी नीतियों ने, एक समय में निजी जमीन के टुकड़ों की सीमा पर लगे प्रतिबंधों में रियायत देने और थोड़े दिनों बाद उस पर कड़ाई बरतने और यही चीज निजी पालतू जानवरों के बारे में लागू करने से किसानों में असंतोष फैला। कई वस्तुओं का उत्पादन गिर गया। केन्द्रीय योजना मंत्रालयों को भंग करके सौ से ऊपर क्षेत्रीय आर्थिक परिषदों के निर्माण से अलग-अलग क्षेत्रीय आर्थिक परिषदों के बीच मुनाफे के लिए होड़ ने उत्पादन में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी। इसके अलावा केन्द्रीय एशिया में बंजर भूमि विकास योजना जैसी जल्दी धनी बनने वाली योजनाओं को लागू करने तथा परम्परागत अनाज फसलों के स्थान पर अमरीकी किस्म की मक्का की फसल उगाने से भी संकट और ज्यादा गहरा गया। इन सबके कारण, मजदूरों और किसानों की आर्थिक स्थिति मे गिरावट आयी।

इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर चली बहस का असर भी सोवियत संघ के नेतृत्व पर पड़ रहा था। युगोस्लाविया के मसले पर ख्रुश्चोव की नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ में जूते पटकने जैसे उसके कारनामों से सोवियत संघ की बदनामी हो रही थी। इन सबका इस्तेमाल करते हुए एक समय के ख्रुश्चोव की संशोधनवादी आम दिशा की प्रशंसा करने वाले उसके घनिष्ठ

सहयोगी और सहभागी ब्रेझनेव और कोसीगिन ने उससे पल्ला झाड़ लिया और "महल" तख्तापलट के जरिये अक्टूबर, 1964 में उसे सत्ताच्युत कर दिया।

जिस तरीके से सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस में
ख्रुश्चोव द्वारा लागू की गई संशोधनवादी कार्य दिशा को "मार्क्सवाद-लेनिनवाद का सृजनात्मक विकास" कहा गया था, उसी तरह इस तख्तापलट को "लेनिनवाद की ओर वापसी" की संज्ञा दी गयी। 1965 के अंत तक क्षेत्रीय आर्थिक परिषदों को भंग कर दिया गया तथा केन्द्रीकृत राज्य आर्थिक योजना तथा प्रबंधन को पुनर्स्थापित किया गया। ख्रुश्चोव द्वारा पार्टी का औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में नकली विभाजन को समाप्त कर दिया गया।

लेकिन ख्रुश्चोव के कदमों को पलटने का अर्थ किसी भी तरह से मार्क्सवाद- लेनिनवाद की ओर वापसी नहीं था। यह सब पूर्ण अराजकता की ओर जाने से बचने का प्रयास था। "लेनिनवाद की ओर वापसी" एक धूम्रावरण था जिसके जरिये वे सोवियत संघ के मजदूर वर्ग और मेहनतकश अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे थे। यह उस समय स्पष्ट हो गया जब सितम्बर, 1965 में कोसिगिन ने अपने "आर्थिक सुधारों" की घोषणा की। ये "आर्थिक सुधार" पूंजीवादी सम्बन्धों की पूर्णता की ओर ले जाने वाले थे। ये "आर्थिक सुधार" जब लागू किये गये तो इन्होंने सोवियत संघ की समूची अर्थव्यवस्था में राज्य इजारेदार पूंजीवाद को कायम किया।

ब्रेझनेव-कोसीगिन गुट ने सत्ता में आने के बाद ख्रुश्चोव द्वारा 20वीं और 22वीं कांग्रेस में प्रस्तुत पूंजीवादी कार्यदिशा को उससे भी आगे बढ़ा दिया। सत्ता में आने के कुछ ही वर्षों में इस गुट ने वह सब कुछ किया जिसे करने के लिए या तो
ख्रुश्चोव के पास समय नहीं था, या वह बेलगाम होकर ऐसा कर नहीं सकता था। सत्तासीन होते ही इस गुट ने "आर्थिक सुधारों" की व्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में जोर-शोर से लागू किया। ये सुधार मुख्यतः लिबरमैन के सुझावों पर आधारित थे। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की विस्तारित बैठकों और सर्वोच्च सोवियत के सत्रों में इन नये सुधारों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किये गये, कानून लागू किये गये और नियम बनाये गये। इन सबमें मुनाफे को सभी चीजों से ऊपर रखा गया और आर्थिक सुधारों को सोवियत संघ की पार्टी की आम नीति बना दिया गया। मार्च, 1965 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्लेनम में ब्रेझनेव ने सोवियत कृषि में लिए जाने वाले "तात्कालिक कदमों" पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया, "सामूहिक और राज्य फार्मों के संचालन के वस्तुगत आकलन में मुनाफे की दर को आधार बनाना चाहिए।" सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सितम्बर, 1965 के प्लेनम में कोसीगिन ने "औद्योगिक उत्पादन में आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाने" सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में जोर दिया कि उद्यमों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने को प्रेरित करने के सबसे अच्छे साधन के बतौर मुनाफे और मुनाफे के कोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। यह उनके "योगदान" करने के आकलन के लिए मुख्य मानक होना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि "कीमतों, मुनाफे, बोनस और कर्जे" के जरिये "आर्थिक प्रोत्साहन" को बढ़ाया जाना चाहिए। इन दोनों प्लेनमों के पारित प्रस्ताव सोवियत संशोधनवादी शासक गुट द्वारा उद्योग और कृषि के सभी क्षेत्रों में पूंजीवाद को प्रोत्साहित करने के मुख्य आधार के बतौर काम करते थे। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 23वीं कांग्रेस में पारित प्रस्ताव खुले तौर पर बताता है कि निकट भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यभारों में एक इस नयी व्यवस्था को हासिल करना है। अगस्त, 1965 में सर्वोच्च सोवियत के सत्र के दौरान कोसीगिन ने जोर दिया कि इस "नयी व्यवस्था" को बिना रोक टोक के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सभी शाखाओं में फैलाना होगा।

उस समय की सांख्यिकी के अनुसार, कुल 5500 औद्योगिक और खनन उद्यम, राज्य फार्मों और कृषि में अन्य राज्य उद्यमों की बड़ी संख्या तथा 4 लाख से ऊपर भण्डार और दुकानें या कहें कि देश की कुल संख्या की तकरीबन आधी इस पूंजीवादी नयी व्यवस्था को अपना चुकी थी।

सोवियत संशोधनवादी नेतृत्वकारी गुट द्वारा "आर्थिक सुधार" के मुखौटे के अंतर्गत "नयी व्यवस्था" को जोर शोर से लागू करने का सार यह है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में चौतरफा तरीके से पूंजीवादी प्रबन्धन को अमल में लाया जाय, समाजवादी उत्पादन सम्बन्धों को खत्म किया जाय और सम्पूर्ण रूप से समाजवादी आर्थिक आधार को तोड़ दिया जाय। इस नयी व्यवस्था ने उद्यमों को यह अधिकार दे दिया कि वे अपने उत्पादन और प्रबन्धन की योजनाओं को स्वतंत्र रूप से तय करें तथा पूंजीवादी उद्यमों की तरह उच्च मुनाफा हासिल करने के लिए उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। इसने उद्यमों के नेताओं को ज्यादा तथा व्यापक सुविधायें दी तथा उनको उत्पादन, वित्त और कार्मिकों के मामले में स्वतंत्र तौर पर निपटने के लिए शक्ति दी गई। "राज्य द्वारा संचालित विनिर्माण उद्यमों को संचालित करने वाली नियमावली" को 1966 में सोवियत संघ में लागू किया गया जिसमें उद्यमों को यह शक्ति दी गयी कि वे उद्यमों की सभी सम्पत्ति के मालिक हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं और उसे खत्म कर सकते हैं। वे "अतिरिक्त" औजार, परिवहन के साधन, कच्चा माल और ईंधन बेच सकते हैं। और अपने परिसरों, गोदामों, औजारों और परिवहन के साधनों को यदि वे अस्थायी तौर पर उपभोग में न हो तो, किराये पर उठा सकते हैं। वे अपनी खुद की पहलकदमी पर अपने "बेकार" की स्थायी परिसम्पत्ति को खत्म कर सकते हैं, योजना से बाहर की पूंजी निर्माण के लिए अपने हाथ में मौजूद फण्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और योजना से बाहर के आर्डरों को पूरा करने हेतु उत्पादन के लिए अपनी खुद की सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नियमावली ने प्रबंधकों को यह शक्ति दे दी कि वे अपनी इच्छा से मजदूरों और स्टाफ के लिए मजदूरी, ग्रेड और बोनस तय कर सकते हैं या बदल सकते हैं, मजदूरों की भर्ती और उनको बर्खास्त कर सकते हैं तथा उनको सजा दे सकते हैं। वह प्रबन्धकों को यह भी शक्ति देती है कि वे खुद उद्यमों के ढांचे और कार्मिकों के बारे में फैसले लें। इस प्रकार, समाजवादी मालिकाने के उद्यमों को पूंजीवादी सुविधाप्राप्त

तबके के मालिकाने वाली पूंजीवादी संस्थाओं में बदल दिया गया। उद्योग और कृषि में काम करने वाले मेहनतकशों के व्यापक हिस्से को अपनी श्रमशक्ति बेचने को मजबूर उजरती गुलामों में तब्दील कर दिया गया।

"नयी व्यवस्था" के लागू होने के परिणामस्वरूप, सोवियत समाज में वर्गीय ध्रुवीकरण लगातार तेज होता जा रहा था। अनेक औद्योगिक उद्यमों, राज्य फार्मों और वाणिज्यिक संस्थानों के मुखिया नये पूंजीवादी तत्व हो गये थे जो भारी तनख्वाहें लेते थे, ऊंचे बोनस प्राप्त करते थे, गैरकानूनी कार्रवाइयों में लिप्त रहते थे, अपनी ताकत का घोर दुरुपयोग करते थे और मेहनतकश अवाम का शोषण और उत्पीड़न करते थे। कई औद्योगिक उद्यमों के प्रबन्धक मशीनों के औजार, जनरेटर जैसे उत्पादन के साधनों को, जो राज्य की सम्पत्ति होते थे, मुनाफे के लिए बेच देते थे।

"नयी व्यवस्था" को आगे बढ़ाने के अतिरिक्त, सोवियत संशोधनवादी गुट ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाये जो स्वतःस्फूर्त तरीके से पूंजीवादी शक्तियों के विकास को प्रोत्साहित करते थे या बढ़ावा देते थे। ब्रेझनेव एण्ड कम्पनी ने सत्ता में आने के बाद जो पहला प्रतिगामी कदम उठाया वह "सामूहिक किसानों" और कृषि में राज्य उद्यमों के कर्मचारियों के निजी मालिकाने वाले जमीन के टुकड़ों और पालतू जानवरों पर लगी पाबन्दियों में और ज्यादा छूट देने का था। इसने निजी पालतू जानवरों की संख्या बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए लम्बी अवधि के कर्जे मुहैय्या कराने के लिए राज्य बैंक को निदेश देने वाले प्रस्ताव पारित किये। परिणामस्वरूप निजी अर्थव्यवस्था रोज ब रोज विकसित होती गयी।

इस काल में, सोवियत संघ मे संशोधनवादी गुट ने खुले बाजार मे कृषि उत्पादों और जानवरों के उत्पादों की कीमतों पर लगे सभी प्रतिबंधों को भी समाप्त कर दिया और जोरशोर से खुला बाजार और खुली प्रतियोगिता को विकसित करने की मुहिम चलाई। इसने निजी व्यापारियों के फलने फूलने के लिए दरवाजा खोल दिया। 1966 के अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार, समूचे सोवियत संघ में 7500 से ज्यादा खुले बाजार हो गये थे। औसतन प्रत्येक महीने करीब 1.7 करोड़ लोग अपने उत्पाद खुले बाजार मे बेचते थे। ये खुले बाजार निजी व्यापारियों के नियंत्रण में होते थे। ये व्यापारी सट्टेबाजी में लगे रहते थे, गलाकाटू कीमतों को लागू करते थे और सभी किस्म की धोखाधड़ी अपनाते थे। सोवियत संशोधनवादी नेतृत्व बड़े खुले बाजारों के लिए भारी मात्रा में फण्ड मुहैय्या कराते थे जिसमें पूंजीवादी प्रबन्धन के लिए अत्यधिक अनुकूल स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक सुविधायें होती थीं। इसके साथ ही "राज्य भंडार" भी मुनाफा कमाने और स्वतंत्र होड़ में लगे रहते थे।

एक समय ख्रुश्चोव ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वह शैतान से भी कर्ज स्वीकार करने को तैयार है। यानी कि "कम्युनिज्म के निर्माण" के लिए अमरीका के पूंजीपतियों से कर्ज की भीख मांग सकता है। उसके चेले उसकी इच्छा को वास्तविकता में तब्दील करने लगे थे। सोवियत संशोधनवादी नेतृत्वकारी गुट ने अमरीका, फ्रांस, इटली और जापान के एकाधिकारी पूंजीवादी गुटों के प्रति "खुले दरवाजे" की नीति लागू की और उनके साथ एक के बाद दूसरे समझौते किये। इसने सोवियत संघ के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने, वहां की जनता को लूटने में उनकी आर्थिक घुसपैठ को प्रोत्साहित किया।

इस सबसे यह जाहिर होता है कि सोवियत समाज में पूंजीवाद की पूर्ण स्थापना हो चुकी थी। संशोधनवादी गुट के "आर्थिक सुधारों" से समाजवाद का कुछ भी लेना-देना नहीं था बल्कि यह समाजवाद और कम्युनिज्म से बेशर्मी भरा विश्वासघात था।

ख्रुश्चोव के बाद ब्रेझनेव और कोसीगिन गुट ने सोवियत संघ में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना को पूर्ण रूप दिया। इसने पहले पार्टी और सरकार पर कब्जा किया। सोवियत संघ के भीतर पूंजीवादी विशेषाधिकार प्राप्त तबके की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का विस्तार किया। इसने पार्टी, सरकार और सेना के साथ-साथ आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में शासक वर्ग की हैसियत प्राप्त कर ली और इस तबके के बीच से एक नौकरशाह एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग उभरा। यह एक ऐसा नया पूंजीपति वर्ग था जो समूची राज्य मशीनरी और पूरी सामाजिक सम्पदा को नियंत्रित करता था।

यह एकाधिकारी नौकरशाह पूंजीपति वर्ग कथनी में समाजवाद और करनी में साम्राज्यवादी व्यवहार करता था। यह दुनिया के बंटवारे के लिए चौतरफा प्रयास शुरू कर चुका था।

ब्रेझनेव के काल में ही सोवियत सामाजिक साम्राज्यवादियों ने अफगानिस्तान में अपनी फौजें तैनात की थीं। वहां पर वे लम्बे समय तक फंसे रहे। उनको अफगानी लोगों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अंतर-साम्राज्यवादी टकराहट के चलते अंततः अमरीकी साम्राज्यवादियों के समर्थन से वहां खड़ी होने वाली इस्लामपंथी ताकतें विजयी हुईं।

ब्रेझनेव के काल के दौरान ही सोवियत संघ के जीवन के हर क्षेत्र में मूलाधार और अधिरचना में और उत्पादन सम्बन्धों में पूंजीवादी पुनर्स्थापना पूरी हो गयी थी और सोवियत संघ एक साम्राज्यवादी देश में तब्दील हो चुका था। लेकिन तब भी वह "समाजवादी देश" का लेबिल लगाये हुए था। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी एक पूंजीवादी पार्टी में तब्दील हो चुकी थी क्योंकि संशोधनवाद और कुछ नहीं पूंजीवादी विचारधारा है।

पूंजीवादी पुनर्स्थापना के बाद समाज में ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ा। मजदूर वर्ग फिर से उजरती गुलाम बन गया। मजदूर-किसान संश्रय टूटा। ग्रामीण इलाकों में नया कुलक वर्ग पैदा हुआ। छोटे से अल्पतंत्र का एकाधिकारी नौकरशाह पूंजीपति वर्ग बना और शक्तिशाली हुआ। राष्ट्रीयताओं को फिर से उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। समाजवादी समाज के दौरान जो राष्ट्रीयताओं को समान अधिकार मिला था वह समाप्त हो गया। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीयताओं के बीच अंतरर्विरोध और गैर रूसी राष्ट्रीयताओं में असंतोष व गुस्सा बढ़ने लगा। रूसी श्रेष्ठता वाला अंधराष्ट्रवाद तेजी से बढ़ा। अल्पसंख्यक एकाधिकारी नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध मजदूरों-किसानों और अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं का गुस्सा कभी-कभी हड़तालों और दंगों में फूट पड़ता था।

समाजवादी दौर में महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुए थे, वे समाजवादी निर्माण में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही थीं। न सिर्फ सोवियत संघ के यूरोपीय हिस्से में बल्कि एशिया वाले हिस्से में जहां अक्टूबर क्रांति से पहले महिलाओं की गुलामी ज्यादा नंगे रूप में थी, वहां महिलाओं को आजादी और समानता मिली थी। लेकिन पूंजीवादी पुनर्स्थापना के बाद महिलाओं की स्थिति फिर से दोयम दर्जे के नागरिक की हो गयी। वे कामकाजी होने के बावजूद घरों के भीतर और बाहर भेदभाव का शिकार होने लगीं।

ब्रेझनेव की मौत के बाद ब्रेझनेव की ही कार्यदिशा को लागू करने वाले थोड़े-थोड़े समय के लिए दो शासक आये और 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के बतौर आया।

उस समय सोवियत संघ में निजी पूंजीपति वर्ग भी काफी मजबूत हो गया था। नौकरशाह इजारेदार पूंजीपति वर्ग के भीतर से यह निजी पूंजीपति वर्ग निकला था। सत्ता में कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक फासिस्ट पार्टी थी। सोवियत राज्य पूंजीवादी फासिस्ट राज्य के बतौर था। वहां के निजी पूंजीपति वर्ग और समाज में पूंजीवादी प्रभाव के विभिन्न निम्न पूंजीवादी तबकों में फासिस्ट राज्य के विरुद्ध एक पूंजीवादी जनवादी राज्य की आकांक्षायें पनप रही थीं। रूसी राष्ट्रीय अहंकारवाद के विरुद्ध विभिन्न राष्ट्रीयताओं के बीच विरोध के स्वर तीव्र से तीव्रतर होते जा रहे थे।

सोवियत संघ में उस समय भी उत्पादन के साधनों का स्वरूप मुख्यतः सामाजिक बना हुआ था। जबकि उसकी अंतर्वस्तु पूंजीवादी हो चुकी थी। अंतर्वस्तु के अनुरूप स्वरूप करने की मांग बढ़ती जा रही थी। उसी समय गोर्बाचोव की 'ग्लासनोस्त' और 'पेरेस्त्रोइका' की नीति अस्तित्व में आयी। यह सोवियत संशोधनवाद द्वारा बेमेल स्वरूप और अंतर्वस्तु को बनाये रखने की आखिरी कोशिश थी।

ग्लासनोस्त के तहत कुछ अधिकार लोगों को दिये गये। पेरस्त्रोइका के तहत आर्थिक क्षेत्र में पुनर्गठन किया गया। निजी पूंजीवाद को और बढ़ावा दिया गया। लेकिन सतह के नीचे जो खलबली मची हुई थी, वह ग्लासनोस्त के साथ ही उभर कर सामने आ गयी। कई राष्ट्रीयताओं में अलग होने की मांग मुखर हो गयी। इसी दौरान, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने को सत्ता से अलग कर लिया और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व का रास्ता खोल दिया गया। अब नौकरशाह इजारेदार पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधियों के एक हिस्से ने इसके विरुद्ध बगावत करके सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। उसी समय निजी पूंजीवाद का खुला पैरोकार बोरिस येल्तसिन सामने आया। और इसके बाद सोवियत संघ के विघटन का रास्ता खुल गया। 1991 में मुख्यतः अपने आंतरिक कारणों से, अपने आंतरिक अंतरर्विरोधों से सोवियत संघ का विघटन हुआ और वहां की अर्थव्यवस्था में स्वरूप और अंतर्वस्तु के अंतरर्विरोध को हल करके खुला पूंजीवाद कायम हो गया।

1991 में सोवियत संघ के विघटन और खुले पूंजीवाद की यात्रा की शुरुआत 1956 में ख्रुश्चोव ने कर दी थी। सोवियत संघ में पूंजीवादी पुनर्स्थापना करने और समूचा संशोधनवादी सिद्धान्त ख्रुश्चोव ने पेश कर दिया था। ब्रेझनेव-कोसीगिन से लेकर गोर्बाचोव तक सभी ने उन्हीं ख्रुश्चोवी संशोधनवादी सिद्धान्त के आधार पर काम किया। सिर्फ समय के साथ बाद के लोगों ने पूंजीवादी पुनर्स्थापना से पैदा होने वाली समस्याओं का व्यावहारिक हल निकालने की कोशिशें की। उनकी इन कोशिशों के परिणामस्वरूप सोवियत संघ निरंतर एक संकट से दूसरे संकट तक चलता रहा और अंततः उसका विघटन हो गया।

ख्रुश्चोवी संशोधनवाद के विरुद्ध संघर्ष और पूंजीवादी पुनर्स्थापना रोकने का सिद्धान्त

ख्रुश्चोवी संशोधनवाद के पैदा होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में एक व्यापक बहस छिड़ गयी। जैसा द्वितीय इंटरनेशनल के पतन के समय में हुआ था कि उस समय की अधिकांश स्थापित सामाजिक जनवादी पार्टियों ने संशोधनवाद का पक्ष लिया था सिर्फ बोल्शेविक पार्टी और कुछ इने गिने व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सही अवस्थिति अपनायी थी, वैसा ही ख्रुश्चोवी संशोधनवाद के साथ हुआ, चीन और अल्बानिया की पार्टियों को छोड़कर दुनिया की अधिकांश स्थापित कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व ने ख्रुश्चोवी संशोधनवाद का पक्ष ग्रहण किया था।

चूंकि लेनिन और स्टालिन के देश में, अक्टूबर क्रांति द्वारा स्थापित प्रथम सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व वाले समाजवादी राज्य में ख्रुश्चोवी संशोधनवाद का चौतरफा और व्यापक हमला हुआ था इसलिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 7 वर्षों तक सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अंदरूनी बहस चलायी। इस दौरान, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन की एकता के मकसद से आवश्यक समझौते भी किये। 1957 में शासक कम्युनिस्ट व मजदूर पार्टियों के सम्मेलन में तैयार किये गये घोषणा पत्र और 1960 में 81 देशों की कम्युनिस्ट व मजदूर पार्टियों के सम्मेलन में जारी किये गये वक्तव्य में उनके समझौते थे। लेकिन इन समझौतों के समय भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी अवस्थिति को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया था। विशेषतौर पर "शांति पूर्ण संक्रमण" के सिद्धान्त पर। लेकिन ख्रुश्चोवी संशोधनवादी गुट सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी को न सिर्फ संशोधनवादी पार्टी में तब्दील कर चुका था, बल्कि वह समाजवादी राज्य को बदल कर पूंजीवादी राज्य में तब्दील कर चुका था। वह

अपनी संशोधनवादी कार्यदिशा को समूचे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन की आम कार्यदिशा बनाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा हुआ था। जिस युगोस्लविया को 1948 में समाजवादी खेमे से बाहर कर दिया गया था, उसे वह समाजवादी देश कहने लगा था। उसने आणविक हथियारों का डर दिखा कर दुनिया की राष्ट्रीय मुक्ति क्रांतियों को डराने की कोशिश की थी। वह अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ सांठगांठ कर रहा था। दूसरी तरफ, वह अल्बानिया की मजदूर पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर पहले तो छिपे तौर पर फिर खुले तौर पर हमला करने लगा। उसने इन पार्टियों के साथ चल रहे विचारधारात्मक-राजनीतिक विवादों को राज्य के स्तर पर पहुंचा दिया। तब तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी इस समझ तक पहुंच चुकी थी कि ख्रुश्चोवी संशोधनवाद को न तो सही मार्क्सवादी-लेनिनवादी दिशा में वापस लाया जा सकता है और न ही सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ऐसे मार्क्सवादी-लेनिनवादी लोग हैं जो साहस पूर्वक मजदूर और मेहनतकश लोगों का आह्वान करके ख्रुश्चोव के पूंजीवादी सदर मुकाम को ध्वस्त करने के लिए तैयार हों।

दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर अमरीकी साम्राज्यवाद राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को कुचल रहा था और समाजवादी देशों को भीतर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। समाजवादी देशों के बीच की किसी भी फूट का वह इस्तेमाल कर सकता था। युगोस्लाविया को वह पहले ही अपने पक्ष में कर चुका था।

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि खुद चीन के अंदर पूंजीवादी तत्व मजबूत होते जा रहे थे। वहां नेतृत्व में पूंजीवादी पथगामी मौजूद थे। चीन में पूंजीवादी पुनर्स्थापना का खतरा सुदूर भविष्य की बात नहीं थी। यह खतरा मुंह बाये सामने खड़ा था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में भी ख्रुश्चोव जैसे लोग मौजूद थे।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेता माओ त्से तुंग ने ख्रुश्चोवी संशोधनवाद के विरुद्ध अंदरूनी संघर्ष चलाते हुए उसके पैदा होने के कारणों को समझने और उनसे सबक निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्हें चीन के भीतर कम्युनिस्ट पार्टी और राज्य में ऐसे पूंजीवादी तत्वों के विरुद्ध संघर्ष करने का विशाल अनुभव था। उन्हें अपने देश के लिए भी पूंजीवादी पुनर्स्थापना को रोकने के रास्ते निकालने थे।

इसीलिए जब उन्होंने यह कहा कि ख्रुश्चोवी संशोधनवाद एक बुरी बात है, लेकिन यह एक अच्छी बात भी है। इस अच्छी बात के कहने का अर्थ यही था कि वे इसके पैदा होने के कारणों की छानबीन करके उससे सबक निकालकर आगे की पीढ़ियों के लिए वह रास्ता निकाल सकेंगे जिससे समाजवादी समाज में पुनर्स्थापना को रोका जा सके।

अपने देश चीन के अंदर पैदा होने वाले पूंजीवादी पथगामियों के विरुद्ध संघर्ष से मिले अनुभव और ख्रुश्चोवी संशोधनवाद के विरुद्ध संघर्ष से मिलाकर उन्होंने पूंजीवादी पुनर्स्थापना को रोकने के तौर तरीके विकसित किये।

ख्रुश्चोवी संशोधनवाद का पैदा होना कोई आकस्मिक या अलग-थलग परिघटना नहीं थी। यह विश्वव्यापी परिघटना का हिस्सा थी। इस होने वाली परिघटना से माओ ने सबक निकाले।

माओ ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर समय-समय पर पैदा होने वाले पूंजीवादी तत्वों के विरुद्ध संघर्ष करके उनको बेनकाब किया था। उन्हें उच्च पदों से हटाने में कामयाब भी हुए थे। लेकिन फिर से नये तत्व उभर कर आ जाते थे। तब उन्होंने ख्रुश्चोवी संशोधनवाद के संघर्ष के दौरान समाजवादी समाज में पूंजीवादी पुनर्स्थापना के कारणों की तलाश की और उसको रोकने के लिए एक आम रूप रेखा प्रस्तुत की।

यह रूप रेखा निम्नलिखित है :

> "पहली बात यह है कि समाजवादी समाज का अध्ययन करते समय विरोधी तत्वों की एकता के मार्क्सवादी-लेनिनवादी नियम को लागू करना आवश्यक है। सभी चीजों में अंतरविरोध का नियम, यानी विरोधी तत्वों की एकता का नियम, भौतिकवादी द्वन्द्ववाद का अत्यंत बुनियादी नियम है। यह नियम हर जगह लागू होता है, चाहे प्राकृतिक विश्व का क्षेत्र हो अथवा मानव समाज या मानव विचार का क्षेत्र। एक अंतरविरोध के विरोधी तत्व परस्पर एकता भी कायम करते हैं और संघर्ष भी करते हैं तथा ये चीजों को गतिशील बनने और बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। समाजवादी समाज इसका अपवाद नहीं है। समाजवादी समाज में दो बुनियादी प्रकार के सामाजिक अंतर्विरोध होते हैं, यानी जनता कि बीच के अंतरविरोध तथा हमारे और दुश्मन के बीच के अंतरविरोध। इन दोनों प्रकार के अंतरविरोधों का सारतत्व बिल्कुल भिन्न है, तथा इन्हें हल करने का तरीका भी भिन्न-भिन्न प्रकार का होना चाहिए। उन्हें सही ढंग से हल करने के परिणामस्वरूप सर्वहारा अधिनायकत्व अधिकाधिक सुदृढ़ बनता जायेगा तथा समाजवादी समाज और अधिक मजबूत और विकसित होता जायेगा। बहुत से लोग विरोधी तत्वों की एकता के नियम को मंजूर अवश्य करते हैं, लेकिन समाजवादी समाज के प्रश्नों का अध्ययन करते समय और उन्हें हल करते समय इस नियम को लागू नहीं कर पाते। वे यह मानने से इंकार करते हैं कि समाजवादी समाज में भी अंतरविरोध होते हैं- न सिर्फ हमारे और दुश्मन के बीच अंतरविरोध होते हैं, बल्कि जनता के बीच भी अंतरविरोध होते हैं- तथा वे यह नहीं जानते कि इन दो प्रकार के सामाजिक अंतरविरोधों के बीच फर्क कैसे किया जाय और उन्हें कैसे हल किया जाय, और इस लिए सर्वहारा अधिनायकत्व के सवाल को सही ढंग से हल नहीं कर पाते।
>
> "दूसरी बात यह है कि समाजवादी समाज एक काफी लम्बे ऐतिहासिक काल तक जारी रहता है। इस समाज में भी वर्गों और वर्ग संघर्ष का अस्तित्व बना रहता है, तथा समाजवादी रास्ते और पूंजीवादी रास्ते के बीच सघर्ष जारी रहता है। केवल आर्थिक मोर्चे पर (उत्पादन के साधनों की मिल्कियत के क्षेत्र में) समाजवादी क्रांति करना अपने आप में अपर्याप्त है तथा उसे सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता। राजनीतिक और विचारधारात्मक क्षेत्रों में भी पूर्ण समाजवादी क्रांति की जानी चाहिए। समाजवाद

और पूंजीवाद के बीच के संघर्ष में "कौन जीतेगा", इसका फैसला करने के लिए काफी लम्बे समय की जरूरत होती है। कुछ दशाब्दियों से काम नहीं चलेगा; सफलता के लिए एक शताब्दी से लेकर कुछ शताब्दियों तक का समय चाहिए। अवधि के प्रश्न पर विचार करते समय, कम समय के बदले ज्यादा समय की तैयारी रखना ज्यादा अच्छा है। प्रयत्न के प्रश्न पर विचार करते समय, इस कार्य को आसान समझने के बदले मुश्किल समझना ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार सोचना और अमल करना ज्यादा फायदेमंद और कम नुकसानदेह होगा। जो कोई भी यह बात देखने में और इसे पूरी तरह समझने में असमर्थ रहता है, वह भारी गलतियां कर सकता है। समाजवाद के ऐतिहासिक काल में, यदि पूंजीवाद की पुनर्स्थापना की रोक-थाम करनी हो, यदि समाजवादी निर्माण को आगे बढ़ाना हो, तथा कम्युनिज्म में संक्रमण के लिए स्थितियां पैदा करनी हों, तो यह जरूरी है कि सर्वहारा अधिनायकत्व को बनाये रखा जाय और समाजवादी क्रांति को अंत तक चलाया जाय।

तीसरी बात यह है कि सर्वहारा अधिनायकत्व का नेतृत्व मजदूर किसान सहयोग के आधार पर, मजदूर वर्ग करता है। इसका मतलब है मजदूर वर्ग द्वारा और उसके नेतृत्व में जनता का प्रतिक्रियावादी वर्गों और व्यक्तियों पर तथा समाजवादी रूपान्तरण व समाजवादी निर्माण का विरोध करने वाले तत्वों पर अधिनायकत्व लागू किया जाना। जनता की पातों में जनवादी केन्द्रीयता पर अमल किया जाता है। हमारे यहां सबसे व्यापक जनवाद पर अमल किया जाता है, जो किसी भी पूंजीवादी राज्य के लिए सम्भावना की सीमा से परे है।

चौथी बात यह है कि समाजवादी क्रांति और समाजवादी निर्माण, दोनों में ही यह जरूरी है कि जनदिशा पर कायम रहा जाय, साहसपूर्वक जनता को जगाया जाय तथा बड़े पैमाने पर जनआंदोलन चलाये जायें। "जनता से लेकर जनता को ही लौटाने" की जनदिशा हमारी पार्टी के समस्त कार्य की बुनियादी दिशा है। यह जरूरी है कि बहुसंख्यक जनता पर पक्का भरोसा रखा जाय, तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुसंख्यक मजदूर-किसान जनता पर पक्का भरोसा रखा जाय। हमें अपने काम में जनता से सलाह-मशविरा करने में निपुण हो जाना चाहिए तथा किसी भी सूरत में उससे नाता नहीं तोड़ना चाहिए। हुक्मरानी और दाता के रवैये के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। अपने विचारों को पूरी तरह और दिल खोलकर जाहिर करना और बड़े पैमाने पर वाद-विवाद करना, क्रांतिकारी संघर्ष के ऐसे महत्वपूर्ण रूप हैं जिन्हें हमारे देश की जनता ने दीर्घकालीन क्रांतिकारी संघर्ष के दौरान जन्म दिया है, संघर्ष के ऐसे रूप हैं जिनमें जनता के बीच के अंतर्विरोधों तथा हमारे और दुश्मन के बीच के अंतरविरोधों को हल करने के लिए जनता पर निर्भर रहा जाता है।

पांचवीं बात यह है कि चाहे समाजवादी क्रांति हो अथवा समाजवादी निर्माण, यह सवाल हल करना जरूरी है कि किस पर निर्भर रहा जाय, किसे अपने पक्ष में किया जाय, और किसका विरोध किया जाय। सर्वहारा वर्ग और उसके हिरावल दस्ते को समाजवादी समाज का वर्ग-विश्लेषण करना चाहिए, दृढ़ता से समाजवादी रास्ता अपनाने वाली वस्तुतः विश्वसनीय शक्तियों पर निर्भर रहना चाहिए, तमाम सहयोगियों को अपने पक्ष में कर लेना चाहिए, तथा समाजवाद के दुश्मनों के खिलाफ समान संघर्ष के दौरान व्यापक जनता के साथ, जिसकी संख्या आबादी के पचानबे फीसदी से ज्यादा है, एकताबद्ध हो जाना चाहिए। देहाती इलाकों में कृषि के सामूहिकीकरण के बाद यह जरूरी है कि गरीब और निम्न मध्यम किसानों पर निर्भर रहा जाय, ताकि सर्वहारा अधिनायकत्व और मजदूर-किसान सहयोग को मजबूत बनाया जा सके, सहज रूप से पैदा होने वाली पूंजीवादी प्रवृत्तियों को परास्त किया जा सके तथा समाजवाद के मोर्चे को मजबूत और इनका विस्तार किया जा सके।

छठी बात यह है कि शहरों और देहातों में, बार-बार व्यापक समाजवादी शिक्षा आंदोलन चलाना जरूरी है। जनता को शिक्षित करने के लिए निरंतर चलाये जाने वाले इन आंदोलनों में, हमें क्रांतिकारी वर्ग शक्तियों को संगठित करने में, उनकी वर्ग चेतना को ऊंचा उठाने में, जनता के बीच के अंतर्विरोधों को सही ढंग से हल करने में, तथा उन सब लोगों को एकताबद्ध करने में जिन्हें एकताबद्ध किया जा सकता है, कुशल होना चाहिए। इन आंदोलनों में यह जरूरी होता है कि समाज विरोधी, पूंजीवादी और सामंतवादी शक्तियों-जमींदारों, धनी किसानों, प्रतिक्रांतिकारियों और पूंजीवादी दक्षिणपंथियों तथा गबनकारियों, भ्रष्टाचारियों और पतनशील लोगों के खिलाफ एक तीव्र शठे-शाठ्यम संघर्ष किया जाय, ताकि उनके द्वारा समाजवाद पर किये गये प्रहारों को चकनाचूर किया जा सके तथा उनमें से अधिकांश लोगों को नया इंसान बनाया जा सके।

सातवीं बात यह है कि सर्वहारा अधिनायकत्व के बुनियादी कामों में एक यह भी है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का सक्रियता के साथ विकास किया जाय। यह जरूरी है कि कृषि को बुनियाद बनाकर और उद्योग को प्रमुख तत्व मानकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास करने की आम नीति के मार्गदर्शन में, उद्योग, कृषि, विज्ञान व तकनालोजी और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का कदम-ब-कदम आधुनिकीकरण किया जाय। उत्पादन की बढ़ोत्तरी के आधार पर यह आवश्यक है कि जनता के रहन-सहन का स्तर कदम-ब-कदम बड़े पैमाने पर ऊंचा उठाया जाय।

आठवीं बात यह है कि समूची जनता की मिलकियत और सामूहिक मिलकियत समाजवादी अर्थव्यवस्था के दो भिन्न रूप हैं। सामूहिक मिलकियत से समूची जनता की मिलकियत में संक्रमण करना एक काफी लम्बी प्रक्रिया है। खुद सामूहिक मिलकियत भी निचले स्तर से ऊंचे स्तर की ओर, छोटे पैमाने से बड़े पैमाने की ओर विकास करती है। जन कम्यून, जिनकी रचना चीनी जनता ने की है, इस संक्रमण के सवाल को हल करने के लिए संगठन का एक अनुकूल रूप है।

नवीं बात यह है कि "सौ फूलों को खिलने दो और सौ विचारों में होड़ होने दो" की नीति का उद्देश्य कला के सिवाय और विज्ञान की प्रगति को बढ़ावा देना तथा एक समृद्ध समाजवादी संस्कृति का विकास करना है। शिक्षा को सर्वहारा राजनीति की सेवा करनी चाहिए और उसे उत्पादक श्रम से मिलाया जाना चाहिए। मेहनतकश जनता को ज्ञान-विज्ञान में माहिर बन जाना चाहिए और बुद्धिजीवियों को शारीरिक श्रम करने की आदत डालनी चाहिए। विज्ञान, संस्कृति, कला और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में सर्वहारा विचारधारा को आगे बढ़ाने और पूंजीवादी विचारधारा को खत्म करने का संघर्ष एक दीर्घकालीन और भीषण वर्ग-संघर्ष है। यह जरूरी है कि सांस्कृतिक क्रांति, वर्ग संघर्ष, उत्पादन के संघर्ष और वैज्ञानिक प्रयोग के

क्रांतिकारी अमल के जरिये मजदूर वर्ग के ऐसे बुद्धिजीवियों का एक विशाल दस्ता बना दिया जाय, जो समाजवाद की सेवा करते हों और "लाल और विशेषज्ञ" दोनों हों, यानी जो राजनीतिक दृष्टि से जागृत हों और व्यावसायिक दृष्टि से सुयोग्य हों।

दसवीं बात यह है कि कार्यकर्ताओं के सामूहिक उत्पादक श्रम में भाग लेने की व्यवस्था को बनाये रखना जरूरी है। हमारे पार्टी कार्यकर्ता और सरकारी कार्यकर्ता साधारण मेहनतकश हैं, जनता के सिर पर सवार लाट साहब नहीं। सामूहिक उत्पादक श्रम में भाग लेकर, हमारे कार्यकर्ता मेहनतकश जनता के साथ व्यापक रूप से निरंतर और घनिष्ठ सम्बन्ध कायम रखते हैं। यह समाजवादी व्यवस्था के लिए बुनियादी महत्व का मुख्य कदम है : इससे नौकरशाही को दूर करने और संशोधनवाद व कठमुल्लावाद की रोकथाम करने में मदद मिलती है।

ग्यारहवीं बात यह है कि मुट्ठीभर लोगों को ऊंचे वेतन देने की व्यवस्था कभी लागू नहीं की जानी चाहिए। पार्टी, सरकार, कारोबारों ओर जन कम्यूनों में काम करने वाले कर्मचारियों की आमदनी तथा व्यापक जनता की आमदनी के फर्क को युक्तियुक्त तरीके से कदम-ब-कदम कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं को अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने और विशेष सुविधाओं का उपभोग करने से रोकना चाहिए।

बारहवीं बात यह है कि एक समाजवादी देश की जन सेनाओं के लिए हमेशा यह जरूरी होता है कि वे सर्वहारा वर्ग की पार्टी के नेतृत्व में और जनता की देखरेख में रहें तथा उन्हें सेना और जनता के बीच तथा अफसरों और सिपाहियों के बीच एकता कायम करते हुए एक जनसेना की गौरवशाली परम्परा को हमेशा कायम रखना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था कायम रखना जरूरी है जिसमें अफसर कुछ समय के बाद नियमित रूप से एक साधारण सिपाही के रूप में काम करें। सैनिक जनवाद, राजनीतिक जनवाद और आर्थिक जनवाद पर अमल करना जरूरी है। साथ ही पूरे देश में मिलीशिया यूनिटों को संगठित और प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि समूची जनता को सैनिक बनाया जा सके। तोप-बंदूकों को हमेशा पार्टी और जनता के हाथ में रहना चाहिए तथा उन्हें कैरियरवादियों का साधन कभी नही बनने देना चाहिए।

तेरहवीं बात यह है कि जनता के सार्वजनिक सुरक्षा संगठन हमेशा सर्वहारा वर्ग की पार्टी के नेतृत्व में, और व्यापक जनता की देखरेख में रहने चाहिए। समाजवाद की उपलब्धियों और जनता के हितों की रक्षा के संघर्ष में व्यापक जनता और सुरक्षा संगठनों के सम्मिलित प्रयत्नों पर निर्भर रहने की नीति लागू की जानी चाहिए, ताकि एक भी खराब आदमी न बच पाये और एक भी अच्छा आदमी गलती से सजा न पाये। जब भी प्रतिक्रांतिकारियों का पता चले तो उनका दमन कर देना चाहिए और जब भी गलतियों का पता चले तो उन्हें सुधार लेना चाहिए।

चौदहवीं बात यह कि विदेश नीति के क्षेत्र में यह जरूरी है कि सर्वहारा अंतरराष्ट्रवाद पर कायम रहा जाय तथा महाराष्ट्राहंकारवाद और राष्ट्रीय अहंवाद का विरोध किया जाय। समाजवादी खेमा अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग और मेहनतकश जनता के संघर्ष की उपज है। इसकी मालिक समाजवादी देशों की जनता तथा साथ ही समूची दुनिया का सर्वहारा वर्ग और मेहनतकश जनता है। हमें सच्चे अर्थों में इस जुझारु नारे को कार्य रूप में परिणत करना चाहिए, "दुनिया के मजदूरो एक हो!" और दुनिया के मजदूरो और उत्पीड़ित राष्ट्रो एक हो आओ!", साम्राज्यवाद व प्रतिक्रियावाद की कम्युनिस्ट विरोधी, जन-विरोधी और प्रतिक्रांतिकारी नीतियों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करो, तथा तमाम उत्पीड़ित वर्गों और तमाम उत्पीड़ित राष्ट्रों के क्रांतिकारी संघर्षो का दृढ़ता से समर्थन करो। समाजवादी देशों के बीच के सम्बन्ध स्वाधीनता व पूर्ण समानता के उसूल तथा आपसी समर्थन और सहयोग के सर्वहारा अंतरराष्ट्रवादी उसूल पर आधारित होना चाहिए। हर समाजवादी देश को अपने निर्माण के लिए मुख्यतः अपने पर ही निर्भर रहना चाहिए। अगर कोई समाजवादी देश अपनी विदेश नीति में राष्ट्रीय अहंवाद पर अमल करता है अथवा इससे भी नीचे गिर कर, दुनिया का बंटवारा करने के लिए बड़े उत्साह के साथ साम्राज्यवाद से सांठ गांठ करता है, तो उसका आचरण पतित और सर्वहारा अंतरराष्ट्रवाद के साथ गद्दारी करने वाला कहलायेगा।

पन्द्रहवीं बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वहारा वर्ग के हिरावल दस्ते के रूप में तब तक मौजूद रहना चाहिए जब तक सर्वहारा अधिनायकत्व मौजूद रहता है। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा संगठन का सर्वोच्च रूप है। सर्वहारा वर्ग अपनी नेतृत्वकारी भूमिका कम्युनिस्ट पार्टी के जरिये ही अदा करता है। सभी विभागों में पार्टी कमेटियों द्वारा नेतृत्व करने की व्यवस्था पर अमल किया जाना चाहिए। सर्वहारा अधिनायकत्व के काल में सर्वहारा पार्टी को सर्वहारा वर्ग और व्यापक मेहनतकश जनता के साथ अपने घनिष्ठ सम्बन्ध को कायम रखना चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए, अपनी जोरदार क्रांतिकारी शैली को कायम रखना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए, मार्क्सवाद-लेनिनवाद की सर्वव्यापी सच्चाई को अपने देश के ठोस अमल के साथ मिलाने के उसूल पर कायम रहना चाहिए तथा संशोधनवाद, कठमुल्लावाद और हर किस्म के अवसरवाद के खिलाफ अविचल संघर्ष करना चाहिए।

"सर्वहारा अधिनायकत्व के ऐतिहासिक सबकों की रोशनी में कामरेड माओ त्से तुंङ ने कहा है :

"वर्ग-संघर्ष, उत्पादन का संघर्ष और वैज्ञानिक प्रयोग ये तीनों एक शक्तिशाली समाजवादी देश के निर्माण के लिए तीन महान क्रांतिकारी आंदोलन हैं। ये आंदोलन इस बात की पक्की गारण्टी करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नौकरशाही से मुक्त रहेंगे तथा संशोधनवाद और कठमुल्लावाद से बचे रहेंगे और हमेशा अपराजेय रहेंगे। ये इस बात की विश्वसनीय गारण्टी करते हैं कि सर्वहारा वर्ग व्यापक मेहनतकश जनता के साथ एकता कायम कर सकेगा तथा एक जनवादी अधिनायकत्व की स्थापना कर सकेगा। यदि इन आंदोलनों के अभाव में, जमींदारों, धनी किसानों, प्रतिक्रांतिकारियों, बुरे तत्वों और किस्म-किस्म के आदमखोरों को अपना सिर उठाने दिया गया तथा हमारे कार्यकर्ताओं ने इन सब बातों की तरफ से अपनी आंखें मूंद लीं और बहुत से आदमियों ने हमारे और दुश्मन के बीच फर्क नहीं किया, बल्कि दुश्मन के साथ सांठ गांठ की और आचरण भ्रष्ट हो गये और हौसला खो बैठे, यदि हमारे कार्यकर्ताओं को इस प्रकार दुश्मन के खेमे में घसीट लिया गया अथवा दुश्मन हमारी पांतों में घुसने में सफल हो गया, तथा यदि हमारे बहुत से मजदूर, किसान और बुद्धिजीवी, दुश्मन की नरम और कठोर कार्यनीतियों

से अपने को बचाने में असमर्थ रहे, तो राष्ट्रव्यापी पैमाने पर प्रतिक्रांतिकारी पुनर्स्थापना होने में, एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी को अनिवार्य रूप से एक संशोधनवादी या फासिस्ट पार्टी बनने में तथा समूचे चीन का रंग बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, शायद कुछ ही वर्ष लगेंगे अथवा एक दशाब्दी लगेगी या ज्यादा से ज्यादा चन्द दशाब्दियां लगेंगी।" ("ख्रुश्चोव का नकली कम्युनिज्म और विश्व के लिए उसके ऐतिहासिक सबक" महान बहस, पृष्ठ-365-370, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, द्वितीय संस्करण, 2004)

जिस समय यह सबक निकाला गया था उस समय यानी 1964 में चीन में समाजवादी शिक्षा आंदोलन शुरू किया गया था। यह एक व्यापक जनांदोलन था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष में बैठे पूंजीवादी पथगामी और विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद निचले स्तर पर उनके सहयोगियों ने इस आंदोलन को महज औपचारिकता तक सीमित कर दिया था। इस जनांदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं और व्यापक जनसमुदाय को समाजवादी शिक्षा और समाजवाद के वर्ग चरित्र के बारे में, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बारे में तथा ऊपर बताये गये सबकों के बारे में शिक्षित करना था। लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष में बैठे पूंजीवादी पथगामी लोगों ने इसको भी वांछित दिशा में आगे नहीं बढ़ने दिया, तब माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरूआत की।

माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत 16 मई 1966 के केन्द्रीय कमेटी के सरकुलर के साथ की। उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता का कारण बताते हुए कहा :

" अतीत में हमने ग्रामीण इलाकों में, फैक्टरियों में, सांस्कृतिक क्षेत्र में संघर्ष छेड़े, और हमने समाजवादी शिक्षा आंदोलन चलाया। लेकिन यह सब समस्या को हल करने में असफल रहे, क्योंकि अपने काले पक्ष का खुले तौर पर, हर पक्ष से और नीचे से पर्दाफाश करने के लिए व्यापक जन समुदाय को जागृत करने के रूप और तरीके नहीं निकाल पाये थे। " (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 9वीं पार्टी कांग्रेस में माओ का उद्धरण, बाब अवेकियान की पुस्तक Mao Tse Tung's Immortal Contribution, Page-27, अनुवाद हमारा)

बाद में माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के उद्देश्य के बारे में बताया जो निम्नलिखित है :

"मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा! मुझे बताओ कि महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का क्या उद्देश्य है? (किसी ने जवाब दिया कि यह पार्टी के भीतर पूंजीवादी पथगामियों के विरुद्ध थी।) पार्टी में पूंजीवादी पथगामियों के विरुद्ध संघर्ष प्रधान कार्यभार है, लेकिन यह इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है विश्व दृष्टिकोण की समस्या को हल करना तथा संशोधनवाद को नेस्तनाबूद करना। केन्द्र ने बार-बार स्वाध्याय के महत्व पर जोर दिया है, क्योंकि विश्व दृष्टिकोण किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, और विचारधारात्मक तौर पर मोड़ने का काम अंदरूनी कारकों पर बाहरी कारकों का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें अंदरूनी कारक की मुख्य भूमिका होती है। यदि विश्व दृष्टिकोण को बदला नहीं गया, हालांकि वर्तमान महान सांस्कृतिक क्रांति में दो हजार पूंजीवादी पथगामियों को हटा दिया गया है, तब अगली बार चार हजार प्रकट हो सकते हैं। हम मौजूदा महान सांस्कृतिक क्रांति में बहुत ऊंची कीमत चुका रहे हैं। दो वर्गों और दो कार्यदिशाओं के बीच संघर्ष को, एक, दो, तीन या चार सांस्कृतिक क्रांतियों द्वारा नहीं तय किया जा सकता, बल्कि मौजूदा महान सांस्कृतिक क्रांति के परिणामों को कम से कम 15 वर्षों तक मजबूत करना होगा। हर सौ वर्षों में दो या तीन सांस्कृतिक क्रांतियां चलायी जानी चाहिए। इसलिए हमें संशोधनवाद को जड़ से उखाड़ने और किसी भी समय संशोधनवाद का प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता को मजबूत करने की बात दिमाग में रखनी चाहिए।" (वही, पृ-281, अनुवाद हमारा)

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति वस्तुतः एक राजनीतिक क्रांति थी। यह अधिरचना के क्षेत्र में होने वाली क्रांति थी। क्रांति का उद्देश्य समाज की समूची अधिरचना में सर्वहारा वर्ग के दृष्टिकोण को स्थापित करना था तथा संशोधनवाद को रद्द करना था। पार्टी, राज्य, विचारधारा, कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा सभी अधिरचना के हिस्से होते हैं। अधिरचना में भी यह संघर्ष पार्टी और राज्यसत्ता के क्षेत्र में केन्द्रित था।

माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति को नितांत आवश्यक और अत्यन्त समयानुकूल बताते हुए नवीं कांग्रेस की केन्द्रीय कमेटी के प्रथम प्लेनरी सत्र में भाषण देते हुए कहा था कि प्रत्यक्षतः हम महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के बगैर नहीं रह सकते थे क्योंकि उस समय हमारा आधार कमजोर था। वह कहते हैं :

"मेरे अनुमान के अनुसार फैक्टरियों की अच्छी खासी संख्या में-मेरा मतलब सभी में या अधिकांश में नहीं है-नेतृत्व असली मार्क्सवादियों और व्यापक मजदूरों के हाथ में नहीं था। ऐसा नहीं है कि फैक्टरियों के नेतृत्व में अच्छे लोग नहीं थे। सचिवों, उपसचिवों और पार्टी शाखाओं की पार्टी कमेटियों में अच्छे सदस्य थे। लेकिन वे ल्यू शाओ ची की नीति -भौतिक प्रोत्साहन देने, मुनाफे को कमान में रखने और सर्वहारा की राजनीति को प्रोत्साहन देने के बजाय बोनस बांटने और ऐसे ही अनेक कामों में लगे हुए थे। फैक्टरियों में वास्तव में बुरे लोग भी थे। ... ... यह दिखाता है कि क्रांति अभी भी पूरी नहीं हुई है।"

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के अंतर्गत सतत क्रांति जारी रखने का सिद्धान्त पेश किया। इस क्रांति ने ऐसे रूप और तरीके प्रस्तुत किये जिसके जरिये पूंजीवादी पुनर्स्थापना के खतरों से निपटा जा सकता है।

हालांकि माओ की मृत्यु के बाद चीन में भी पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हो गयी लेकिन तब भी इसने समाजवादी समाज में पूंजीवादी पुनर्स्थापना के कारणों को समझकर उसको रोकने और कम्युनिज्म की तरफ आगे बढ़ने का सिद्धान्त पेश किया। इस अर्थ में यह मार्क्सवाद-लेनिनवाद के शस्त्रागार में एक बड़ा योगदान है। माओ का यह योगदान मार्क्सवाद के विकास के इतिहास में तीसरा मील का पत्थर है।

आगे भविष्य में जो भी समाजवादी क्रांतियां होंगी, वे पूंजीवादी पुनर्स्थापना को रोकने में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के सैद्धान्तिक योगदान से मदद लेकर ही कामयाब हो सकती हैं। जहां क्रांति नहीं हुई हैं वहां भी पार्टी गठन और निर्माण में 'स्व' के विरुद्ध संघर्ष और संशोधनवाद को पराजित करने के कारण महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की उपादेयता और प्रासंगिकता है।

ख्रुश्चोवी संशोधनवाद द्वारा पूंजीवादी पुनर्स्थापना का सारसंकलन करते हुए माओ ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद को विकसित किया, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा की ऊंचाई तक पहुंचाया। माओ विचारधारा का केन्द्रीय तत्व महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति है।

■■■